THE CORE IAS

INDIA'S FIRST INSTITUTE DEDICATED TO ANSWER WRITING

अख़बार सार

WWW.THECOREIAS.COM

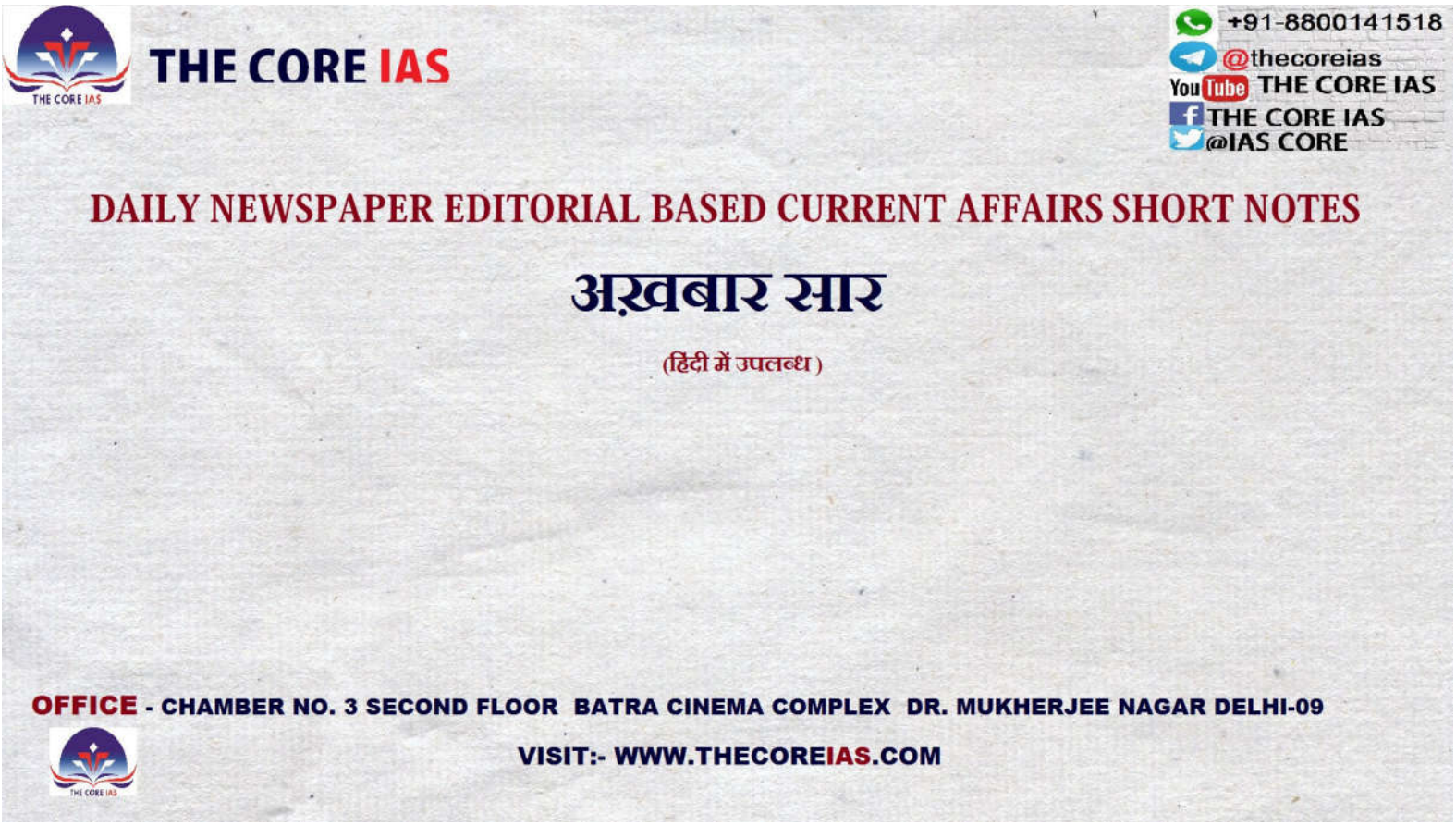

SCAN QR CODE FOR WEBSITE
WWW.THECOREIAS.COM

1.कूड़ा फेंकने की शिकायत पर 160 खाली प्लॉटों का रद किया गया आवंटन

- खाली प्लॉटों में कचरा डालना और जलाना अब मालिक के लिए महंगा साबित हो सकता है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) के निर्देश पर दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम (डीएसआइआइडीसी)

USE IN PAPER 2-GOVERNANCE,3-ENVIRONMENT POLICY

2.सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी होने पर चिंता जताई, मांगी रिपोर्ट

- देश भर की जेलों में क्षमता से अधिक 67 फीसद कैदी होने पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ मामलों के निपटारे के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत बताई है। शीर्ष अदालत ने विचाराधीन समीक्षा समितियों (यूटीआरसी) को 2019 के पहले छह महीने में हर महीने बैठक करने का निर्देश दिया है। समितियों से राज्य में विधि सेवा अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।

USE IN PAPER2-JAIL REFORM ,GOVERNANCE

3.पूर्व सूचना आयुक्त ने सरकार पर लगाया कानूनी रूप से धमकाने का आरोप

- पूर्व सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सूचना आयोग अपने खिलाफ सरकार द्वारा दायर याचिकाओं के खतरे का सामना कर रहा है। उन्होंने इस मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से हस्तक्षेप करने की मांग की।
- राष्ट्रपति को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा है कि ओछी याचिकाएं दायर की जा रही हैं, जिनका मकसद निश्चित रूप से जीतना नहीं है बल्कि 'लक्ष्य' को धमकाने का है, ताकि वह किसी संगठन या व्यक्ति के खिलाफ बोलने जैसी सार्वजनिक गतिविधियों से तौबा कर ले। इस संदर्भ में आचार्युलु ने भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़े दो आदेशों का हवाला भी दिया है।
- आचायरुलु ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सूचना आयुक्त शैलेष गांधी के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें उन्होंने जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वालों के नाम उजागर करने को कहा था। रिजर्व बैंक ने केंद्रीय सूचना आयोग के एक अन्य आदेश को भी चार जुलाई को चुनौती दी थी, जिसमें स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के विदेशी दानदाताओं की जानकारी उजागर नहीं करने पर सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव ने रिजर्व बैंक के सीपीआइओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आचार्युलु ने सवाल किया, 'सूचना आयुक्त के तौर पर जब मैं भारत सरकार का हिस्सा हूं और जब भारत सरकार खुद मेरे आदेशों के खिलाफ लड़ती है तो मेरी रक्षा कौन करेगा?'

USE IN PAPER 2-GOVERNANCE,RTI,CIC

4.मिड डे मील में लापरवाही पर दिल्ली समेत छह राज्यों पर जुर्माना

- शीर्ष कोर्ट ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और जम्मू एवं कश्मीर को एक-एक लाख रुपये भुगतान करने को कहा है। इन राज्यों पर सरकार संचालित स्कूलों में मिड डे मील योजना की निगरानी और पौष्टिक होने के लिए बनाए गए चार्ट के साथ ऑनलाइन लिंक तैयार करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाया गया है।

USE IN PAPER 2-GOVERNANCE, SCHOOL SYSTEM,NUTRITION

5.अब बिजनेस वीजा का 15 साल का विस्तार

- भारत ने बिजनेस वीजा का अधिकतम 15 साल तक का विस्तार करने की सुविधा देने का फैसला किया है। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत यह विस्तार एक बार में पांच साल के लिए हुआ करेगा। इसके

अलावा, विदेशियों के लिए नियमित वीजा को आपात स्थिति में चिकित्सा श्रेणी में भी भारत में रहते हुए ही बदला जा सकेगा।

- केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब पांच साल के बाद भी बिजनेस वीजा का विस्तार हो सकता है। इसका विस्तार अधिकतम 15 साल के लिए हो सकता है। इसके अलावा, भारत सरकार देश में आए किसी विदेशी के वीजा को आपात स्थिति में चिकित्सा वीजा में परिवर्तित कर सकती है।

USE IN EASE OF DOING BUSINESS

6.सरकार ने सेवा वेतन बढ़ाने की सेना की मांग ठुकराई

- क्या है सैन्य सेवा वेतन
- सैन्य कर्मियों की विशिष्ठ सेवा स्थितियों और मुश्किलों के मद्देनजर सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी) प्रदान किया जाता है। देश में इसकी शुरुआत छठे वेतन आयोग ने की थी। हालांकि यूरोपीय देशों में सैन्य बलों के लिए एमएसपी की अवधारणा काफी प्रचलित रही है।

7.मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार ने कैविएट दाखिल की

- महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सरकार ने कहा है कि अगर मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली कोई याचिका दायर होती है तो कोर्ट एकतरफा रोक का आदेश देने से पहले सरकार का पक्ष सुने। महाराष्ट्र सरकार बांबे हाई कोर्ट में एक दिसंबर को ही कैविएट दाखिल कर चुकी है।
- वकील निशांत केतेश्वर की ओर से दायर कैविएट में कहा गया है, 'महाराष्ट्र सरकार को बिना सूचना के इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि 30 नवंबर 2018 को अधिनियम जारी करने वाली महाराष्ट्र सरकार अकेली अधिकृत पार्टी है, इसलिए कोई भी आदेश देने से पहले उसका पक्ष जरूर सुना जाए।
- क्या होती है कैविएट
- यह भी एक प्रकार की याचिका है। इसे उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई से पहले इसलिए दायर किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टी के खिलाफ एकतरफा कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं हो।

PRELIMINARY, GOVERNANCE,RESERVATION

8.सरकारी बैंकों की और बिगड़ सकती है स्थिति

- रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह छह दिसंबर को सरकारी सिक्योरिटीज की खरीद के जरिये 10,000 करोड़ रुपये सिस्टम में डालेगा ताकि तरलता सुधर सके। बैंक के अनुसार तरलता की मौजूदा स्थिति की समीक्षा आधार पर सिस्टम में बेहतर प्रवाह के लिए ओपन मोर्केट ऑपरेशन (ओएमओ) के जरिये 10,000 करोड़ रुपये डाले जाएंगे। आरबीआइ के इस कदम से आइएलएंडएफएस ग्रुप की कंपनियों के डिफॉल्ट होने से पैदा हुए तरलता संकट को घटाने में मदद मिलेगी।

USE IN PAPER 3-FINANCE,BANKING,FISCAL POLICY

9.कंपनियों को विदेश में डायरेक्ट लिस्टिंग की अनुमति संभव

- बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की एक समिति ने मंगलवार को सलाह दी कि भारतीय कंपनियों को विदेशी शेयर बाजारों में और विदेशी कंपनियों को भारतीय शेयर बाजारों में डायरेक्ट लिस्टिंग की अनुमति दी जाए। अभी भारतीय कंपनियां डिपॉजिटरी रिसीप्ट के जरिये विदेशी

बाजारों में सूचीबद्ध हो सकती हैं और विदेशी कंपनियां भी इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट के जरिये भारतीय बाजारों में सूचीबद्ध हो सकती हैं.

USE IN PAPER 3-SEBI,MARKETING

10.ईरान ने फारस की खाड़ी से तेल निर्यात रोकने की धमकी दी

- ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ कड़ा रुख जाहिर किया है। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वह ईरान को कच्चा तेल निर्यात करने से नहीं रोक सकता। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ईरान फारस की खाड़ी के रास्ते अंतरराष्ट्रीय तेल निर्यात नहीं होने देगा। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि अमेरिका, ईरान को भारत, यूरोप और चीन से दूर करने के प्रयास कर रहा है।

USE IN WEST ASIA POLICY,ENERGY

11.बैटियों के कचरे से साफ हो सकेगा प्रदूषित पानी

- खराब हो चुकी बैटियों का कचरा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने बेकार बैटियों में मौजूद पदाथोर्ं के उपयोग से एक नया उत्पाद विकसित किया है, जो बैटियों के कचरे के निपटारे के साथ-साथ प्रदूषित पानी के शोधन में भी मददगार हो सकता है।
- खराब बैटियों से निकाले गए मैग्नीज-ऑक्साइड, एक्टिवेटेड कार्बन और कैल्शियम एल्जिनेट को मिलाकर कैब-मोएक के दाने बनाए गए हैं। पशुपालन उद्योग से निकलने वाले प्रदूषित जल में मौजूद टायलोसिन और पी-क्रेसॉल के अवशेष पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जल में मौजूद इन अवशेषों के शोधन में कैब-मोएक के दानों को विशेष रूप से उपयोगी पाया गया है।
- मुर्गी पालन और सुअर पालन उद्योग में ग्रोथ-एजेंट के रूप में टायलोसिन का मेक्रोलाइड एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग विशेष रूप से बढ़ा है। इसे बनाने वाले कारखानों से निकले अपशिष्टों को जलस्नोतों में बहाने के कारण उनमें टायलोसीन पाया जाता है। इसी तरह जानवरों के मल और धुलाई से निकले दूषित पानी में भी कैंसर के लिए जिम्मेदार पी-क्रसॉल नामक पदार्थ मौजूद होता है।
- 10 घंटे में 99.99 फीसद प्रदूषक साफ : लगभग 0.4 मिलीमीटर आकार, बड़े सतह क्षेत्रफल और अत्यधिक रंध्रीय प्रकृति वाले कैब-मोएक दानों की टायलोसिन और पी-क्रेसॉल को हटाने की दक्षता 99.99 प्रतिशत तक पाई गई है। कैब-मोएक दानों के उपयोग से 10 घंटे में जल में मौजूद इन प्रदूषकों को पूरी तरह हटाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इन दानों के भौतिक और रासायनिक गुणों का परीक्षण करने पर पाया है कि पांच बार उपयोग करने के बावजूद प्रदूषक हटाने की इनकी क्षमता कम नहीं होती।
- अभी यह विधि लाई जाती है प्रयोग में : अपशिष्ट जल की उपचार प्रक्रिया के दौरान उसमें उपस्थित जैविक या विषाक्त पदाथोर्ं को हटाने के लिए दानेदार एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग किया जाता है। एक्टिवेटेड कार्बन में अन्य अवशोषक पदाथोर्ं को मिलाकर इसकी सोखने की क्षमता में सुधार हो सकता है। इस शोध में मैग्नीज-ऑक्साइड और एल्जिनेट से तैयार किए गए कैब-मोएक दाने एक्टिवेटेड कार्बन की तुलना में अधिक प्रभावी पाए गए हैं। एल्जीनेट या एल्जिनिक अम्ल सरगासम और एस्कोफिलम नामक भूरे समुद्री शैवालों में प्रचुर मात्र में पाया जाता है, जिनका उपयोग भारी धातुओं को हटाने के लिए सक्रिय पदार्थ के रूप में होता है। एल्जिनेट का निष्कर्षण भी अपेक्षाकृत आसान होता है।

USE IN ENERGY EFFICIENCY,POLLUTION

12.लद्दाख की पूगा घाटी में भू-तापीय ऊर्जा की संभावना सबसे अधिक

- लद्दाख की पूगा घाटी में स्थित भू-तापीय क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख स्नोत हो सकता है। पिलानी स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं के एक ताजा अध्ययन में यह बात उभरकर आयी है।लद्दाख की पूगा घाटी, जम्मू-कश्मीर के छूमथांग, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, छत्तीसगढ़ के तातापानी, महाराष्ट्र के उन्हावारे और उत्तरांचल के तपोबन जैसे भू-तापीय ऊर्जा से जुड़े आंकड़ों का नौ मापदंडों के आधार पर विश्लेषण किया है।
  USE IN HYDRO THERMAL

EDITORIAL

1.जी-20 में भारत का बढ़ता महत्व

- जटिल वैश्विक कूटनीतिक दांवपेचों के बीच अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आयोजित जी-20 देशों का 13वां शिखर सम्मेलन वैश्विक व्यापार, डब्ल्यूटीओ में सुधार, रोजगार, निवेश, संरक्षणवाद, आतंकवाद और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के साथ संपन्न हो गया। वैश्विक व्यापार को लेकर चल रही तनातनी के बीच यह राहत की बात रही कि जी-20 देशों ने एक स्वर में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में ढांचागत सुधार पर हामी भरी। संगठन के देशों ने बेहिचक स्वीकार भी किया कि डब्ल्यूटीओ वृद्धि और रोजगार सृजन के अपने उद्देश्यों को हासिल करने में विफल रहा है। यह संभव है कि आने वाले वक्त में इसको रोजगारोन्मुख बनाने की पहल तेज हो।
- **नौ-सूत्रीय एजेंडा**
- जी-20 शिखर सम्मेलन भारत के लिए इस अर्थ में ज्यादा महत्वपूर्ण रहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक अपराधियों के खिलाफ पेश नौ-सूत्रीय एजेंडे को संगठन के सभी देशों ने गंभीरता से लिया और माना कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों को प्रवेश देने और सुरक्षित पनाहगाह पाने से रोकने के लिए एक तंत्र विकसित करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नौ सूत्रीय एजेंडे में संगठन के सभी देशों से आग्रह भी किया कि आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए कानूनी प्रक्रिया में सहयोग के साथ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन और यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम के सिद्धांतों को पूर्णत: एवं प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने की जरूरत है। भारत के कई रसूखदार आर्थिक अपराध को अंजाम देकर दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अगर संगठन के सभी देश इस दिशा में ठोस पहल करते हैं तो सूचना के बेहतर आदान-प्रदान के जरिये भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा।
- गौर करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक चिंताओं को साझा करते हुए इस मंच का भारत के हित में शानदार सदुपयोग किया है। उन्होंने जहां एक ओर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से साझा मसलों पर गंभीर विमर्श कर हिंद-प्रशांत क्षेत्र को साझा आर्थिक वृद्धि वाला क्षेत्र बनाने की अपनी वचनबद्धता पर प्रतिबद्धता जताई वहीं चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भारत के इस मत का समर्थन कराने में सफल रहे कि संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूटीओ जैसे अन्य संस्थानों में ढांचागत सुधार की जरूरत है।
- **12 साल बाद त्रिपक्षीय वार्ता**
- प्रधानमंत्री मोदी की पहल से भारत, चीन और रूस के बीच 12 साल बाद दूसरी बार त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जो कि इन देशों के बीच संबंधों के पुनमरूल्यांकन, विश्वास बहाली और क्षेत्रीय शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले इन तीनों देशों के नेताओं के बीच 2006 में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी। आने वाले

वक्त में इस वार्ता के शानदार आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। गौर करें तो वुहान बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच यह चौथी मुलाकात है। बार-बार मुलाकात और संवाद ने दोनों देशों के रिश्तों में मिठास घोली है। उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग दोनों ने एक स्वर में स्वीकार किया कि नियमित संवाद से दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती मिली है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में दोनों देश जटिल सीमा-विवाद को भी सुलझाने में सफल रहेंगे। भारत के लिए चीन और रूस से बेहतर संबंध रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय शांति और आर्थिक सुधार को गति देने के लिए बेहद आवश्यक है। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियों गुतेरस के बीच पर्यावरण को लेकर गंभीर विचार-विमर्श हुआ और पेरिस पर्यावरण समझौते पर एंटोनियों गुतेरस ने भारत के रुख की प्रशंसा की।

- उल्लेखनीय है कि पेरिस समझौते के तहत भारत ने 2030 तक पर्यावरण के लिए घातक गैसों का उत्सर्जन 35 प्रतिशत तक घटाने की घोषणा की है। इसके अलावा पर्यावरण की सुरक्षा के निमित्त भारत और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर एलायंस बनाया है जिसमें 121 अन्य देशों को भी जोड़े जाने की तैयारी है। इन देशों में पहुंचने वाली सूर्य की किरणों का लाभ लेते हुए उनसे ऊर्जा पैदा की जाएगी। यहां जानना आवश्यक है कि गत वर्ष जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में आयोजित जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने जी-20 के सदस्य देशों से अमेरिका के अलग होने के बावजूद भी पेरिस जलवायु करार को कड़ाई से लागू करने की अपील की और कहा कि पेरिस समझौता अपरिवर्तनीय है और उससे पलटा नहीं जा सकता। भारत आज भी अपनी पुरानी प्रतिबद्धता पर कायम है।
- **2022 में मेजबानी करेगा भारत**
- प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्ते मजबूत करने की पहल के साथ आतंकवाद से निपटने के संयुक्त प्रयासों पर भी चर्चा की। अच्छी बात है कि दोनों पक्षों ने आतंकवाद और कट्टरवाद के साथ-साथ रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर सहमति जताई है। भारत के लिए यह बड़ी उपलब्धि है कि वह 2022 में अगले जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2022 में भारत अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा।
- **ठोस रोडमैप का अभाव**
- जी-20 के 13वें शिखर सम्मेलन का मूल्यांकन करें तो यह विचार-विमर्श तक ही सीमित रहा। उसके द्वारा मौद्रिक, वित्तीय और संरचनात्मक नीतियों पर तालमेल बिठाने और कर चोरी रोकने के संदर्भ में कोई रोडमैप नहीं खींचा गया। इस सम्मेलन में उम्मीद थी कि जी-20 के देश आर्थिक मुद्दों विशेष रूप से असंतुलित विकास, वैश्विक मांग में कमी और ढांचागत समस्याओं से निपटने की चुनौती को सामने रख किसी ठोस समझौते को आकार देंगे, लेकिन सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रहे। इसके अलावा काला धन से निपटने, टैक्स मामले में पारदर्शिता लाने, निवेश प्रवाह बढ़ाने, अर्थव्यवस्था के लिए मुक्त आवाजाही पर जोर देने, विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता और कॉरपोरेट टैक्स की चोरी रोकने के लिए नीतिगत उपाय पर भी गौर नहीं फरमाया गया। सदस्य देशों द्वारा नीतिगत समन्वय और सहयोग की दिशा में आगे बढ़कर वैश्विक वित्तीय बाजार की स्थिरता के लिए मुद्रानीति को और प्रभावी बनाने पर भी गंभीरता नहीं दिखाई गई। उम्मीद थी कि सदस्य देश मौजूदा आर्थिक ठहराव से उबरने

और विश्व में रोजगारोन्मुख माहौल निर्मित करने के लिए सरकारी खर्च और वित्तीय अनुशासन के मध्य संतुलन स्थापित करने की दिशा में ठोस नीति बनाएंगे, लेकिन वे ढुलमुल रवैया अपनाते दिखे। सम्मेलन में संरक्षणवादी उपायों को वापस लेने के साथ कर नियमों को बेहतर बनाने की दिशा में भी किसी तरह की ठोस पहल नहीं हुई। अगर इस पर चर्चा हुई होती तो नि:संदेह विकासशील देशों का भला होता।

- **उभरते देशों की चुनौती**
- मौजूदा समय में जी-20 की सबसे बड़ी चुनौती उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में रोजगार का संकट खत्म करना, धीमी वृद्धि के अलावा यूरोप में वित्तीय बाजार के बिखराव को रोकना और उसके मद्देनजर बैंकिंग यूनियन को निर्णायक ढंग से लागू करना है। इसके अलावा पूंजी प्रवाह में व्यापक उतार-चढ़ाव, कठिन वित्तीय हालात और उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में घट-बढ़ को थामना भी उसकी जिम्मेदारी है। यह तथ्य है कि आंतरिक जटिलताओं और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है जिसके कारण न केवल विकासशील देशों, बल्कि विकसित देशों में भी निजी निवेश कम हो रहे हैं। यह जी-20 के विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि वे उन विकासशील देशों में जहां जीडीपी के समक्ष अनुमानित और वास्तविक ऋण काफी ऊंचा है वहां आर्थिक सुधारों का न सिर्फ समर्थन करें, बल्कि उसमें सहभागी भी बनें। उचित होता कि इस सम्मेलन में जी-20 के सदस्य देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में गति लाने और ढांचागत परियोजनाओं के विकास के लिए कर्ज की विशेष सुविधा की उपलब्धता के लिए कोई नीति बनाए होते, लेकिन इस तरह की पहल नहीं हुई। संगठन के देशों को समझना होगा कि निवेश, वित्तीय नियमन और ढांचागत परियोजनाओं के पोषण से जुड़ी समस्याओं का जब तक अंत नहीं होगा तब तक जी-20 समूह अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करेगा। सच तो यह है कि इन्हीं उद्देश्यों को हासिल करने के लिए ही जी-20 समूह का गठन हुआ था। अच्छी बात यह है कि भारत हर शिखर सम्मेलन में वैश्विक समस्याओं पर चिंता जाहिर कर जी-20 को उसका लक्ष्य याद दिला रहा है।

2. तेल विश्व की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली वस्तु है।

- इसकी वजहें भी हैं। तेल अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, इसका अपना सैन्य महत्व है और कुछ इलाकों में ही इसके भंडार सिमटे हैं। यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतें कितनी होंगी? क्योंकि तेल की दुनिया में अनिश्चितता ही निश्चित है। भू-राजनीति और भू-अर्थव्यवस्था में तेल का अव्वल स्थान है। इसका सामरिक महत्व भी है। यह अपने बूते पर दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था, भू-राजनीति और आंतरिक राजनीति में उथल-पुथल मचा सकता है। फ्रांस के दंगे इसके ताजा उदाहरण हैं। .
- फ्रांस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त कर लगाकर इनकी कीमतें बढ़ा दीं। महंगाई के कारण जीवन-यापन में आ रही मुश्किलों से वैसे ही वहां हर कोई जूझ रहा था। सरकार के कदम ने इस आग में घी डालने का काम किया। परिवहन व्यवस्था मुख्यत: तेल पर आधारित है और वहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या भी नगण्य है, इसलिए लोग पेट्रो-पदार्थों में हुई मूल्य-वृद्धि के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को बल-प्रयोग करना पड़ा। मौत, गिरफ्तारियों और घायलों का सिलसिला शुरू हो गया। जाहिर तौर पर, इससे राष्ट्रपति मैक्रों की साख और लोकप्रियता में भी गिरावट आई है।.

- फ्रांस सरकार की मानें, तो यह सब वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किया गया था। सरकार की सोच थी कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाकर कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। मगर जनता की नजर में बढ़ी कीमतों का नुकसान वास्तविक है और यह वर्तमान में उन्हें प्रभावित कर रहा है, जबकि वादा भविष्य का किया गया है, जो अभी संभावना मात्र है। नजरिये के इसी अंतर ने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया।.
- इतिहास से सबक लेना बुद्धिमानी मानी जाती है। अतीत के अनुभवों का हमें लाभ लेना ही चाहिए। साल 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद ईरान में तेल के दामों में भारी उछाल आया था। चूंकि तेल का दाम वैश्विक होता है, इसलिए इसका प्रभाव विश्व के तमाम देशों के पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्यों पर पड़ा। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रह सका। 1980 के राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर को जिस हार का सामना करना पड़ा, उसका बड़ा कारण पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी-लंबी कतारें और पेट्रोल व डीजल के मूल्यों में वृद्धि को भी माना जाता है।.
- ईरान संकट के दौरान राष्ट्रपति कार्टर ने तेल के महत्व को देखते हुए 'कार्टर डॉक्ट्रिन' की घोषणा की थी। यह आने वाले दशकों में पश्चिम एशिया में अमेरिकी-रणनीति की बुनियाद बनी। इस डॉक्ट्रिन के तहत अमेरिका ने घोषणा की कि वह पश्चिम एशिया में अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए बल प्रयोग का विकल्प अपना सकता है। आने वाले दशकों में अमेरिका ने कई बार ऐसा किया भी। खाड़ी युद्ध और इराक पर सैन्य हमला इसके उदाहरण हैं। जिमी कार्टर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बने रोनाल्ड रेगन ने भी इस 'डॉक्ट्रिन' को आगे बढ़ाते हुए सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप करने की घोषणा की। इसके पहले 1976 में अमेरिका और सऊदी घराने के बीच इसी प्रकार का एक समझौता हुआ था, जिसने 'पेट्रो-डॉलर्स' को जन्म दिया था।.
- अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्विटर के माध्यम से सऊदी अरब पर दबाव बनाकर तेल के दाम को संतुलित व नियंत्रित रखने के प्रयास को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। पेट्रो-पदार्थों के दामों को नियंत्रित रखना राष्ट्रपति ट्रंप की घरेलू राजनीतिक मजबूरी है। तेल के दाम में अप्रत्याशित तेजी को रोकने के लिए जरूरी है कि सऊदी अरब का उत्पादन लगातार बना तो रहे ही, साथ-साथ प्रतिबंध की वजह से ईरान द्वारा निर्यात किए जा रहे तेल की मात्रा में आई कमी की भरपाई भी वह करे। पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बाद घटे घटनाक्रम ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के हाथों को मजबूत किया है। सऊदी अरब 'ओपेक प्लस' यानी ओपेक देश व रूस के उत्पादन में कमी या सीमित रखकर तेल के दाम में वृद्धि करने में जुटा है। यह उसकी आर्थिक मजबूरी भी है, क्योंकि उसके बजट में अनुमानित राजस्व के लक्ष्य को पाने के लिए तेल का मूल्य लगभग 80 डॉलर प्रति बैरल होना चाहिए। फ्रांस के आंदोलन को देखते हुए संभावना है कि राष्ट्रपति ट्रंप तेल के दाम को एक निर्धारित दायरे में रखने के लिए और कारगर कार्रवाई कर सकते हैं।.
- बहरहाल, भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र के कारण आने वाले समय में तेल के दामों में अस्थिरता के बने रहने की आशंका है। ओपेक प्लस द्वारा उत्पादन-स्तर को बनाए रखना या इसमें कटौती का फैसला ओपेक की कल यानी 6 दिसंबर को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से छूट की छह माह की समय-सीमा भी मई महीने की शुरुआत में खत्म हो जाएगी। इस प्रतिबंध से पहले ईरान 20 लाख बैरल से अधिक तेल का निर्यात कर रहा था। जाहिर है, ओपेक प्लस के फैसलों का सीधा प्रभाव तेल की वैश्विक कीमतों पर पड़ेगा।.

- भारत इन तमाम घटनाक्रमों से सीधा-सीधा प्रभावित होगा। पिछले कुछ महीनों में देश में तेल के बढ़ते दामों से स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई थी। हालांकि अभी तेल की कीमतों में गिरावट से लोगों को राहत मिली है। लेकिन तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों को प्रभावित करने की भारत की क्षमता फिलहाल नगण्य है। ऐसे में, हमारी यही अपेक्षा होगी कि ओपेक प्लस विश्व अर्थव्यवस्था पर तेल के मूल्यों के दूरगामी असर को ध्यान में रखकर एक संतुलित फैसला ले। खासकर, जब इन सब फैसलों का असर लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है, तो जरूरी यह भी है कि इस अवधि के दौरान केंद्र सरकार जो भी फैसला करे, वह घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिरता और राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के दृढ़ संकल्प के साथ लिया जाए। क्या ऐसा हो सकेगा?.